CEDSI TIMES

Your Skilling Partner...

एनडीडीबी के अध्यक्ष श्री मीनेश शाह को डॉ कुरियन पुरस्कार प्रदान किया गया

श्री अमित शाह, माननीय केंद्रीय गृह मामलों और सहकारिता मंत्री ने 18 मार्च 2023 को गांधीनगर में 49वें डेयरी उद्योग सम्मेलन में श्री मीनेश शाह, अध्यक्ष, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) को 14वें डॉ कुरियन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया।

श्वेत क्रांति के जनक डॉ वर्गीज कुरियन के नाम पर, भारतीय डेयरी संघ द्वारा स्थापित पुरस्कार श्री मीनेश शाह को भारतीय डेयरी उद्योग के विकास और विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया।

श्री मीनेश शाह ने कहा कि मैं आईडीए का डॉ कुरियन पुरस्कार पाकर वास्तव में सम्मानित महसूस कर रहा हूं, जिनके साथ मैंने कई वर्षों तक काम किया। अपने गुरु के नाम पर पुरस्कार प्राप्त करना एक बहुत ही खास अहसास है और इससे मुझे गहरा संतोष मिलता है कि मैं वर्तमान संदर्भ में डॉ कुरियन के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में सक्षम हूं।

उत्पादन में गिरावट के बीच कर्नाटक सहकारी समितियों ने पैकेट का आकार घटाया

बेंगलुरु को नंदिनी ब्रांड के दूध के प्रमुख आपूर्तिकर्ता कोलार को-ऑपरेटिव मिल्क यूनियन लिमिटेड (कोमूल) ने 16 मार्च से शुरू होने वाले ग्रामीण उत्पादकों से दूध की खरीद की कीमत 2 रुपये बढ़ाकर 31.90 रुपये से 33.90 रुपये करने का एकतरफा फैसला लिया।

हालांकि, कोमुल ने कर्नाटक मिल्क फेडरेशन (केएमएफ) द्वारा नवंबर 2022 में 2 रुपये की कीमत बढ़ाने के कारण खरीद लागत में वृद्धि को पारित नहीं किया।

इस साल फरवरी से, कोमूल ने अपनी सुविधाओं में पैक किए गए उच्च वसा वाले समृद्धि दूध की मात्रा में "मात्रा संशोधन" भी किया है और बड़े पैमाने पर बेंगलुरु में बेचा जाता है। एक लीटर के पैकेट में दूध की मात्रा घटाकर 900 एमएल कर दी गई है, जबकि 500 एमएल के पैकेट में दूध की मात्रा घटाकर 450 एमएल कर दी गई है, जिसकी कीमत क्रमश: 50 रुपये और 24 रुपये है।

केंद्र एनडीडीबी के तहत महानंद डेयरी का प्रभार लेने के लिए बातचीत कर रहा है

महाराष्ट्र सरकार की डेयरी 'महानंदा' को केंद्र सरकार जल्द ही नियंत्रित करने वाली है।

इस आशय का संकेत डेयरी विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने दिया, जिन्होंने राज्य विधानसभा को सूचित किया कि राज्य सरकार डेयरी चलाने में असमर्थ है। इसलिए, महानंदा डेयरी को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) को सौंप दिया जाएगा, जो एक वैधानिक निकाय है जो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अधीन है और इसका मुख्य कार्यालय आणंद (गुजरात) में है।

"हमने एनडीडीबी को शामिल करने का फैसला किया क्योंकि हम महानंदा डेयरी को एक निजी ट्रस्ट या कंपनी को नहीं सौंपना चाहते थे। बातचीत अंतिम चरण में है" श्री पाटिल ने सामाजिक चर्चा के दौरान विधानसभा में कहा।

भारत को दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी निर्यातक बनने का लक्ष्य रखना चाहिए: अमित शाह

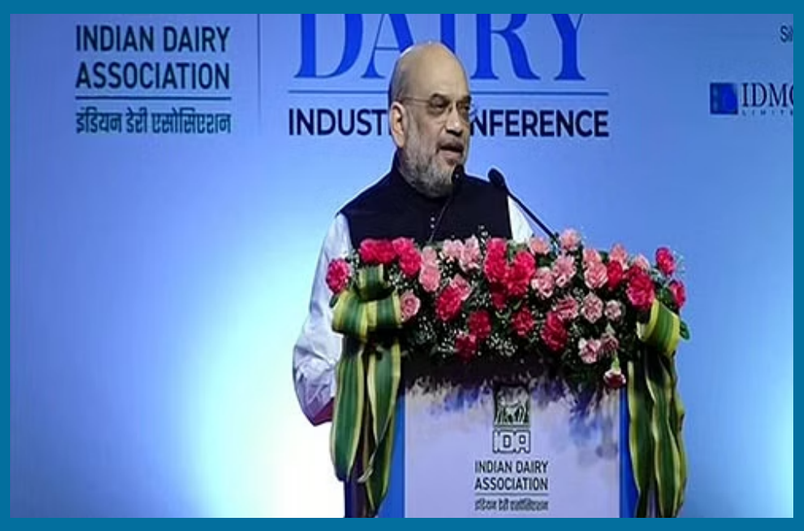

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बनकर संतुष्ट नहीं होना चाहिए बल्कि सबसे बड़ा डेयरी निर्यातक बनने का लक्ष्य भी रखना चाहिए। इंडियन डेयरी एसोसिएशन (आईडीए) द्वारा गांधीनगर में आयोजित 49 वें डेयरी उद्योग सम्मेलन में "दुनिया के लिए भारत डेयरी: अवसर और चुनौतियां" विषय पर बोलते हुए।

शाह ने कहा कि भारत की दूध प्रसंस्करण क्षमता करीब 12.6 करोड़ लीटर प्रतिदिन है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा कि 1970 से 2022 तक, भारत की जनसंख्या में चार गुना वृद्धि हुई है, लेकिन दूध उत्पादन में दस गुना वृद्धि हुई है।

अमित शाह ने यह भी कहा कि डेयरी एक वैश्विक उद्योग है, लेकिन यह रोजगार सृजन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का एक तरीका और कुपोषण और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों के समाधान के लिए भारत की जनसंख्या के विशाल अवसर प्रदान करता है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि उनका सहयोग मंत्रालय 2033-34 तक 330 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन के लक्ष्य के साथ देश भर के दो लाख गांवों में दूध उत्पादक समितियों की स्थापना करेगा।

अपने भाषण में अमित शाह ने कहा कि डेयरी एक वैश्विक व्यवसाय है, लेकिन भारत जैसे 130 करोड़ की आबादी वाले देश में यह रोजगार का स्रोत है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का विकल्प है, कुपोषण की समस्या का समाधान है, और महिला सशक्तिकरण के लिए अपार संभावनाओं वाला क्षेत्र।

भारत के डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल के बारे में बोलते हुए, शाह ने कहा कि पिछले एक दशक में भारतीय डेयरी क्षेत्र में प्रति वर्ष 6.6% की वृद्धि हुई है और केंद्र इसे और भी आगे बढ़ाने के लिए पहल कर रहा है और इसके लिए, उन्होंने कहा, सरकार है गांवों में दो लाख डेयरी सहकारी समितियां स्थापित करने की योजना है, जो भारत के डेयरी क्षेत्र को 13.80% तक बढ़ावा देगी, जिससे वैश्विक दूध उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 33% हो जाएगी। उन्होंने कहा, "हमारा डेयरी निर्यात मौजूदा स्तर से कम से कम पांच गुना अधिक होगा।"

फरवरी में चारा महंगाई दर 24 फीसदी पर

कुछ राहत के संकेत दिखाते हुए, थोक मूल्य सूचकांक आधारित चारा मुद्रास्फीति फरवरी 2023 में मामूली रूप से घटकर 24 प्रतिशत हो गई, जो जनवरी में 29.29 प्रतिशत की तुलना में कम है, आधिकारिक आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है।

हालांकि, नवीनतम चारा मुद्रास्फीति अभी भी पिछले साल फरवरी में दर्ज आंकड़े (11.55 प्रतिशत) से अधिक है। बढ़े हुए चारे की कीमतें चिंता का कारण हैं क्योंकि वे दूध की कीमतों को बढ़ावा देते हैं, जो कि पिछले साल कई बार बढ़ चुकी है।

WPI-based fodder inflation at 24 per cent in February, 2023

Commodity Name	Commodity Code	Weight (%)	Index Value		Inflation (%)
			Feb-22	Feb-23	
All commodities	1000000000	100	145.3	150.9	3.85
Fodder	1102030008	0.5314	192.1	238.8	24.31
p. Manufacture of prepared animal feeds	1301160000	0.3563	204.1	208.2	2.01
(i) Gola & similar Cattle Feed	1301160001	0.21073	200.5	217.4	8.43
(ii) Rice Bran Extract	1301160002	0.03918	182.5	199.7	9.42
(iii) Soya preparations excluding oil	1301160003	0.01012	197.6	179.6	-9.11
(iv) Cotton seed oil cake	1301160004	0.06115	207.6	195.4	-5.88
(v) Mustard oil cake	1301160005	0.03512	245.3	192.9	-21.36

थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में 0.5314 प्रतिशत वजन वाले चारे की कीमतें नवंबर, 2021 से बढ़ रही हैं। डब्ल्यूपीआई आधारित चारा मुद्रास्फीति पिछले साल नवंबर में अपने उच्चतम स्तर 30.93 प्रतिशत पर पहुंच गई थी। दिसंबर 2022 में, चारा मुद्रास्फीति का आंकड़ा 30.56 प्रतिशत था। चारा मुद्रास्फीति का उच्च स्तर समग्र WPI मुद्रास्फीति में गिरावट के विपरीत है, जो फरवरी 2023 में दो साल के निचले स्तर 3.85 प्रतिशत पर आ गया है।

चारा आपूर्ति को आसान बनाने के लिए, सरकार ने 2023-24 के दौरान 100 चारा प्लस किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की स्थापना की घोषणा की थी। इनमें से अधिकतम 16 की योजना गुजरात में है, इसके बाद कर्नाटक (11 एफपीओ), बिहार (9), केरल (9), और राजस्थान (8) का स्थान है।

जम्मू-कश्मीर सरकार ने एचएडीपी के तहत चारे की कमी को कम करने के लिए 129.05 करोड़ रुपये की पहल की घोषणा की

जम्मू और कश्मीर, कृषक समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार और क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए पशुधन पालन की क्षमता को पहचानते हुए, समग्र कृषि विकास कार्यक्रम (एचएडीपी) के तहत कई उपाय शुरू किए हैं।

अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस), कृषि उत्पादन विभाग, अटल डुल्लू के अनुसार, एक शीर्ष समिति ने एचएडीपी के तहत एक व्यापक योजना तैयार की है, जिसकी राशि 129.05 करोड़ रुपये है, ताकि यूटी में चारे की कमी को 80 प्रतिशत तक कम किया जा सके। इस कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य कृषि और पशुधन क्षेत्रों को बढ़ाना है और किसानों को उत्पादकता, लाभप्रदता और क्षेत्र की समग्र आर्थिक प्रगति को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता, उन्नत बीज और तकनीकी मार्गदर्शन जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों से लैस करना है।

जम्मू-कश्मीर में इस क्षेत्र की 70 प्रतिशत से अधिक आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी आजीविका के लिए कृषि और संबंधित व्यवसायों पर निर्भर करती है। वर्षों से, पशुधन पालन सतत और समान विकास के लिए एक महत्वपूर्ण विकास इंजन के रूप में उभरा है, जो कृषक समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने के लिए महत्वपूर्ण है।

पशुधन क्षेत्र बाजरा की मांग को बढ़ावा दे सकता है

माना जाता है कि बाजरा मानव जाति द्वारा पालतू पहली फसलों में से एक है; इसलिए, उन्हें अक्सर हमारे पूर्वजों की सुपर फसल कहा जाता है। इनमें तीन प्रमुख (ज्वार, मोती, उंगली) और छह छोटी फसलें (बार्नयार्ड, प्रोसो, फॉक्सटेल, कोदो, ब्राउनटॉप और छोटी) शामिल हैं। लगभग 60 साल पहले तक, भारत में बाजरा उगाए जाने वाले प्रमुख अनाज थे। हरित क्रांति से पहले, बाजरा कुल खेती वाले अनाज का लगभग 40 प्रतिशत था (गेहूं और चावल से अधिक योगदान)। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चावल और गेहूं के उत्पादन को बढ़ावा देने वाली सरकारी नीतियों के साथ-साथ बदलते आहार पैटर्न के कारण बाजरा के रकबे और इसके उत्पादन में भारी गिरावट आई है।

गहराते जलवायु संकट और पर्यावरणीय तनाव ने जलवायु-स्मार्ट फसलों को बढ़ावा देकर फसल विविधीकरण की आवश्यकता को बढ़ा दिया है। पोषण, कृषि और जलवायु चुनौतियों के जवाब में बाजरा की भूमिका को स्वीकार करते हुए, संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष (IYoM) के रूप में घोषित किया।

मकई (मक्का) की तुलना में रागी में खनिज, प्रोटीन और सुपाच्य फाइबर के मामले में पोषक तत्व अधिक होते हैं और इसलिए इसे मकई के पूरक के रूप में डेयरी मवेशियों को खिलाया जा सकता है। घास या साइलेज - हरे चारे का संरक्षित रूप बनाने के लिए भी फसल एक अच्छा विकल्प है। इसी तरह, प्रोसो बाजरा का पोषक मूल्य पशुओं के चारे के लिए उपयोग किए जाने वाले अन्य अनाजों के समान होता है और इसलिए दूध उत्पादन से समझौता किए बिना बछड़ों, डेयरी गायों और छोटे जुगाली करने वालों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। चूंकि बाजरा चारा उत्पादन की प्रति इकाई कम पानी का उपयोग करता है और गर्मी के साथ-साथ सूखे को भी सहन करता है, उनकी खेती उन क्षेत्रों में किफायती है जहां पर्यावरण की स्थिति, विशेष रूप से वर्षा और तापमान, अन्य अनाज उगाने के लिए बहुत कठोर हैं।

अगले पृष्ठ पर जारी रखें

दूसरे पेज से जारी

पोल्ट्री फीड में बाजरे के दानों को शामिल करने में भी हाल के वर्षों में तेजी आई है। अध्ययनों ने संकेत दिया है कि ब्रायलर आहार में बाजरा के साथ मकई के प्रतिस्थापन के परिणामस्वरूप पक्षियों की वृद्धि और फ़ीड दक्षता में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

बाजरा उत्पाद प्रणालियों के माध्यम से फसल-पशुधन एकीकरण में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना, विशेष रूप से पारिस्थितिक रूप से नाजुक वर्षा वाले क्षेत्रों में, चारे की कमी को पूरा करने, पशु पोषण और प्रदर्शन को बढ़ाने के साथ-साथ हमारी खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। दोहरे उद्देश्य वाली किस्मों के लिए गुणवत्तापूर्ण बीज श्रृंखला को मजबूत करना, हरे बायोमास से घास/साइलेज बनाने पर फ्रंटलाइन प्रदर्शन और किसानों को चारा उद्योग के साथ बाजार से जोड़ना भी प्राथमिकताओं में होना चाहिए। बाजरा आधारित पशु चारा तैयार करने के लिए तकनीकी बैकस्टॉपिंग के साथ स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने से दीर्घावधि में इन सुपर फसलों के उत्पादन को बढ़ावा मिल सकता है।

सीईडीएसआई ने ASCI के सहयोग से डेयरी विकास विभाग, असम सरकार के अधिकारियों के लिए TOT का आयोजन किया है

सीईडीएसआई ने छोटे जुगाली करने वाले पशुओं पर पशु सखियों को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए ITC सुनेहरा कल मिशन के लिए तीन दिवसीय अपस्किलिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम न केवल पशु सखियों को समुदाय में उनकी आजीविका में योगदान देने के साथ-साथ क्षेत्र में छोटे जुगाली करने वाले किसानों की आजीविका में सुधार करने में मदद करता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में नस्ल चयन, भोजन, स्वास्थ्य प्रबंधन और विपणन सहित छोटे जुगाली करने वाले प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जाएगा। कार्यक्रम राजस्थान राज्य के कोटा और झालावाड़ जिलों में आयोजित किया गया था।

टीओटी कार्यक्रम एक बड़ी सफलता थी, और अधिकारियों ने प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त मूल्यवान अंतर्दृष्टि और कौशल के लिए आभार व्यक्त किया। सीईडीएसआई को असम में डेयरी क्षेत्र के विकास को समर्थन देने के अपने चल रहे प्रयासों के हिस्से के रूप में इस कार्यक्रम का आयोजन करने पर गर्व है, और इस क्षेत्र में सतत और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए हितधारकों के साथ काम करना जारी रखने की आशा करता है।

सीईडीएसआई ने सहज दुग्ध उत्पादक कंपनी के फील्ड पदाधिकारियों के लिए एक अपस्किलिंग का आयोजन किया है

15 और 16 मार्च को अलीगढ़ में सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के फील्ड पदाधिकारियों के लिए तीन दिवसीय अपस्किलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 28 मध्य-वरिष्ठ क्षेत्र पदाधिकारियों ने भाग लिया और डेयरी उत्पादन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया। कार्यक्रम को प्रतिभागियों को डेयरी मूल्य श्रृंखला की गहन समझ प्रदान करने और उनके संचालन की दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस करने के लिए डिज़ाइन किया गया था।

कार्यक्रम वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा प्रायोजित किया गया था। कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य डेयरी मूल्य श्रृंखला को अधिक ऊर्जा-कुशल बनाना और डेयरी उद्योग में स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना था। प्रशिक्षण कार्यक्रम में महत्वपूर्ण दूध खरीद पहलुओं, डेयरी अपशिष्ट प्रबंधन और जीएचजी शमन सहित कई विषयों को शामिल किया गया।

हम कौन हैं?

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत भारतीय कृषि कौशल परिषद (ASCI) के तत्वावधान में काम करने वाली एक स्वायत्त संस्था "भारत में डेयरी कौशल के लिए उत्कृष्टता केंद्र (CEDSI)", किसानों की आजीविका के सशक्तिकरण और बेहतरी में मदद करने के लिए, वेतनभोगी कर्मचारी, और डेयरी मूल्य श्रृंखला में अन्य हितधारक।

सीईडीएसआई सदस्यता उद्योग के नेताओं, नीति निर्माताओं, विकास चिकित्सकों, डेयरी वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, छात्रों और किसानों को डेयरी उद्योग के लिए आसन्न महत्व के मुद्दों पर बहस और चर्चा करने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करेगी।